

न्यूज़ हुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिशेष भूमि के मुद्रिकरण के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रिकरण निगम (NLMC) के गठन की मंजूरी दी

- राष्ट्रीय भूमि मुद्रिकरण निगम (National Land Monetization Corporation: NLMC) को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपये और पेड-अप शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये होगी।
 - इससे पहले इसे बजट 2021-22 में प्रस्तावित किया गया था।
 - भूमि मुद्रिकरण, परिसंपत्ति मुद्रिकरण कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है।
- NLMC की भूमिका:
 - रणनीतिक विनिवेश या बंद होने की प्रक्रिया से गुजर रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) की अधिशेष भूमि और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण करना और इस संबंध में सहायता प्रदान करना।
 - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की पहचान करने में सलाह और सहायता देना। साथ ही, उनका पेशेवर और कुशल तरीके से मुद्रिकरण करना।
 - भूमि मुद्रिकरण से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियों के भंडार (repository) के रूप में काम करना। साथ ही, परिसंपत्ति मुद्रिकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और तकनीकी सलाह प्रदान करना।
 - यह भूमि परिसंपत्ति के पेशेवर प्रबंधन और मुद्रिकरण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध कराएगा।
- परिसंपत्ति मुद्रिकरण क्या है: इसका आशय सरकारी परिसंपत्तियों (एसेट्स) के मुद्रिकरण से है। इसके तहत सरकार उपयोग रहित या अधिशेष सरकारी परिसंपत्तियों को एक निश्चित समय के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देती है। बदले में निजी क्षेत्र के पक्षकार उन परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, उनसे लाभ कमाते हैं तथा सरकार को अग्रिम धन या राजस्व संबंधी अधिकार देते हैं।
 - इससे पहले, सरकार ने चार वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रिकरण पाइपलाइन (NMP) का शुभारंभ किया था। इससे लगभग 6 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है।

अवसंरचना परिसंपत्ति मुद्रिकरण चक्र



भारत में "WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM)" की स्थापना को स्वीकृति

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में 'WHO-GCTM' (यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र) की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "मेजबान देश समझौते (Host Country agreement)" पर हस्ताक्षर किए हैं।
 - इसकी स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत की जाएगी। यह विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम और सुदूर स्थित एकमात्र वैश्विक केंद्र (कार्यालय) होगा।
- GCTM के लाभ:
 - इससे वैश्विक स्तर पर आयुष प्रणालियों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
 - इससे भारत को पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।
 - यह पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेगा।
 - इससे प्रासंगिक तकनीकी क्षेत्रों में डेटा आधारित विश्लेषण और प्रभाव आकलन के लिए मानदंडों, मानकों, और दिशा-निर्देशों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।
 - इससे पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में आवश्यक क्षमता निर्माण करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सहायता मिलेगी।
- पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय:
 - योग से जुड़े पेशेवरों के स्वैच्छिक प्रमाणन हेतु योजना आरंभ की गयी है।
 - योग प्रमाणन बोर्ड (Yoga Certification Board: YCB): इसे दुनिया भर में योग से जुड़े पेशेवरों के ज्ञान और कौशल में तालमेल, गुणवत्ता और एकरूपता लाने के लिए स्थापित किया गया है।
 - आयुष प्रणाली के बारे में प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने के लिए 31 देशों में आयुष सूचना प्रकोष्ठ (AYUSH Information Cell) की स्थापना की गई है।

○ ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक चिकित्सा क्या है?

- यह उन स्वास्थ्य संबंधी पद्धतियों, दृष्टिकोणों, ज्ञान और विश्वासों को संदर्भित करता है, जिनमें किसी रोग के इलाज, निदान और रोकथाम या बेहतरी के लिए पादपों, आध्यात्मिक उपचार के तरीकों आदि को शामिल किया जाता है।
- इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) और सोवा रिम्पा शामिल हैं।



रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत चाय निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश में है

- यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर भारत, चाय के लिए वैकल्पिक निर्यात बाजार विकसित करना चाहता है। इस वैकल्पिक निर्यात बाजार में इराक, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ट्यूनीशिया जैसे देशों को शामिल किया जा सकता है।
 - वर्तमान में अकेले रूस ही, देश से कुल चाय निर्यात का 20 प्रतिशत से अधिक आयात करता है।
 - कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (CIS) में शामिल देश भी भारत के महत्वपूर्ण चाय निर्यात गंतव्य हैं।
- भारत में चाय का उत्पादन:
 - वर्ष 2019 में, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक था।
 - भारत, सी.टी.सी. चाय, ऑर्थोडॉक्स टी, ग्रीन टी और ऑर्गेनिक टी सहित विविध प्रकार की चाय का उत्पादन करता है।
 - चाय अधिनियम, 1953 के तहत भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह बोर्ड विकासात्मक व विनियामक कार्य करता है तथा प्रचार संबंधी गतिविधियों को भी देखता है।
- चाय की खेती के लिए जलवायु की स्थिति:
 - तापमान: चाय की खेती के लिए आदर्श तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि, चाय की वृद्धि के लिए न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
 - वर्षा: चाय की खेती के लिए 150-250 से.मी. वर्षा की आवश्यकता होती है।
 - मिट्टी: चाय के पौधों को चूने और लोहे के साथ मिश्रित उपजाऊ पहाड़ी मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होनी चाहिए।
 - भूमि: चाय की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली भूमि की आवश्यकता होती है। चाय के पौधों के लिए पानी का ठहराव उपयुक्त नहीं है।

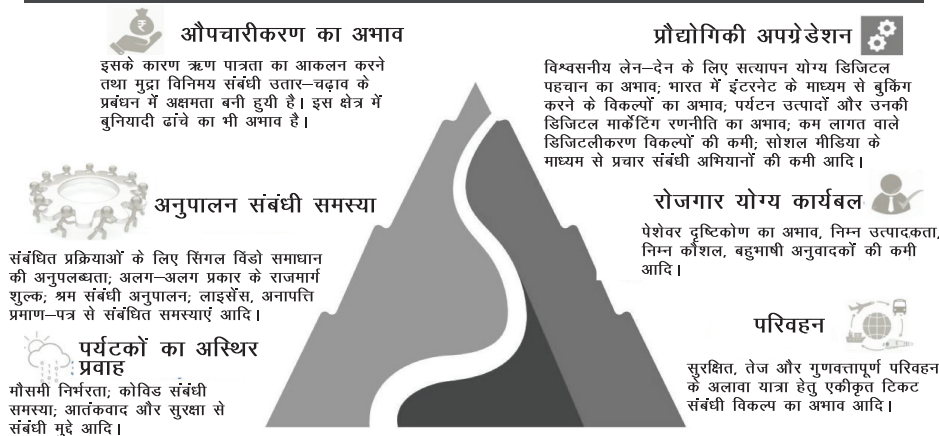
स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल (Commonwealth Independent States: CIS)

- CIS की स्थापना वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी।
- इसमें 12 सदस्य देश शामिल हैं: आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान।

पर्यटन मंत्रालय (MoT) ने 'राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (NDTM)' की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणियां आमंत्रित की है

- पर्यटन मंत्रालय ने NDTM की स्थापना के लिए वर्ष 2021 में एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था। इसका उद्देश्य NDTM के संपूर्ण दायरे को निर्धारित और परिभाषित करना था।
 - NDTM के तहत पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पर्यटन क्षेत्र में सूचना और सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाकर की जाएगी।
 - इस मिशन का विज़न डिजिटल समाधान उपलब्ध कराना है। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच मौजूदा सूचना संबंधी अंतराल को दूर किया जाएगा।
- भारत में पर्यटन क्षेत्र:

भारतीय पर्यटन क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां



- वर्ष 2028 तक भारतीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को आगंतुक विदेशी पर्यटकों (visitor exports) से 50.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होने की संभावना व्यक्त की गई है। वर्ष 2018 में यह 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- भारत, वर्ष 2018 में यात्रा और पर्यटन में निवेश के मामले में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा देश था। वर्ष 2018 में इस क्षेत्र में 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ था, जो देश में कुल निवेश का 5.9% था।
- भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय:
 - राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन: पर्यटन के क्षेत्र में संधारणीयता को बनाए रखने के लिए।
 - नेशनल मिशन ऑन टूरिज्म MSMEs: स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए।
 - स्वदेश दर्शन योजना
 - 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान' अर्थात् 'प्रसाद' (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive: PRASHAD) योजना: इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है।
 - पर्यटन पर्व: इसके तहत भारतीयों को भारत में पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नए खनिजों के खनन की अनुमति दी गयी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (यानी MMDR अधिनियम) की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने संबंधी खान मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य ग्लूकोनाइट, पोटाश, पन्ना (एमराल्ड), प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स (PGM), एन्डेलुसाइट, सिलिमेनाइट और मॉलिब्डेनम जैसे कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्धारित करना है।
 - ग्लूकोनाइट और पोटाश का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है।
 - PGM, एन्डेलुसाइट और मॉलिब्डेनम महंगे खनिज हैं। इनका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है।
- इस संशोधन से होने वाले लाभ:
 - नए खनिजों के खनन की अनुमति से इनके आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी।
 - भारत में पहली बार इन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। इससे खनन और विनिर्माण क्षेत्र के लिए कई अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
 - इससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही, इससे कृषि क्षेत्र को भी समर्थन प्राप्त होगा।
- इससे पहले, खनिज संबंधी रियायतें प्रदान करने की एक नई व्यवस्था लाने के लिए वर्ष 2015 में MMDR अधिनियम में संशोधन किया गया था।
 - बाद में, खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में इसमें दुबारा संशोधन किया गया था।

○ रॉयल्टी: यह कोई कर नहीं होता है। यह उस भूमि का किराया होता है जिस पर खदान स्थित होती है, अथवा यह सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि से खनिज निकालने के विशेषाधिकार की कीमत होती है।

अन्य सुर्खियाँ

 उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (Fertiliser Control Order, 1985)	○ कृषि मंत्रालय ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में संशोधन किया है। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि यदि सील पैक बैग से लिए गए उर्वरक के सैंपल्स, मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो राज्य, विनिर्माणकर्ताओं और डीलर्स दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ○ इसके तहत डीलर्स को स्टॉक के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बनाए रखने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इससे स्पष्ट रूप से रियल टाइम में स्टॉक की स्थिति, ओपनिंग बैलेंस, प्राप्तियों आदि का पता लगाया जा सकेगा। ○ इस आदेश के अनुसार, यदि कोई विनिर्माता या खुदरा विक्रेता घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरक की मार्केटिंग करता है या बिक्री के लिए आयात करता है, तो उस पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (The National Bank for Financing Infrastructure and Development: NaBFID)	○ रिजर्व बैंक ने कहा है कि NaBFID को आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित और प्रबंधित किया जाएगा। ○ NaBFID के बारे में: ➤ यह बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institution: DFI) है। ➤ DFI की स्थापना दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए की जाती है। इसके तहत शामिल ऋण जोखिम इतना ज्यादा होता है कि वाणिज्यिक बैंक और अन्य साधारण वित्तीय संस्थान उसे पूरा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ➤ यह एक निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिसके अध्यक्ष को RBI के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अरब डॉलर-रुपये की स्वेप नीलामी आयोजित की है (Reserve Bank of India (RBI) conducts a \$ 5 billion dollar-rupee swap auction)	○ इस नीलामी के तहत, RBI ने बैंकों को 5.135 अरब डॉलर की बिक्री की है। साथ ही, RBI ने बैंकों से स्वेप निपटान अवधि के अंत में डॉलर वापस खरीदने पर सहमति भी व्यक्त की है। ➤ यह नीलामी प्रक्रिया, RBI की तरलता प्रबंधन पहल का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रणाली में डॉलर का अंतर्वाह (इनफ्लो) किया जाता है और प्रणाली से रुपया बाहर निकाला जाता है। ○ इससे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम होगा और रुपया मजबूत होगा, जो पहले ही एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है।
 उद्यम पूंजीपति (Venture capitalists)	○ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्यम पूंजीपतियों ने भारत के स्टार्ट-अप तंत्र और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ○ एक उद्यम पूंजीपति एक प्रकार का निवेशक होता है। वह जोखिम भरे स्टार्ट-अप व्यवसायों में निवेश करता है। एक उद्यम पूंजी निवेशक एक ऐसे उद्यमी को धन प्रदान करता है जिसके पास पर्याप्त बैंक ऋण या पूंजी के अन्य स्रोतों तक पहुंच नहीं होती है। ➤ उद्यम पूंजीपति अक्सर उस व्यवसाय की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, जिसमें वे निवेश करते हैं।
 साइड-चैनल अटैक (Side-Channel Attacks: SCAs)	○ भारतीय शोधकर्ताओं ने IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) उपकरणों पर साइड-चैनल अटैक्स (SCA) को रोकने के लिए एक निम्न ऊर्जा खपत वाली सुरक्षा चिप का निर्माण किया है। ○ SCA का उद्देश्य सिस्टम की टाइमिंग संबंधी सूचना, बिजली की खपत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीक जैसी चीजों को मापकर क्रिप्टोग्राफिक कीज़, प्रोग्राइट्री मशीन लर्निंग मॉडल और पैरामीटर जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना है। ➤ इन्हें साइडबार अटैक या इम्प्लीमेंटेशन अटैक के रूप में भी जाना जाता है। ➤ सामान्यतया इनका पता लगाना और उनसे बचाव करना कठिन होता है। ○ SCAs के प्रकार: टाइमिंग अटैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (EM) अटैक, एकाॅस्टिक, पावर, ऑप्टिकल, मेमोरी कैश, हार्डवेयर संबंधी कामियां।
 "द एंड्योरेंस" नामक खोया हुआ जहाज एक सदी बाद मिला (Lost ship 'The Endurance' found after a century)	○ "द एंड्योरेंस" अंटार्कटिक के खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शेकल्टन का जहाज था। इस जहाज से उन्होंने अंटार्कटिका भूमि को पार करने का पहला प्रयास किया था। ○ उनका जहाज समुद्री बर्फ के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह वर्ष 1915 में शेकल्टन और उनके सहयोगियों को बाहर निकलने के दौरान डूब गया था। ○ एक सदी के बाद, अब इसे वेडेल सागर में 3,008 मीटर की गहराई पर देखा गया है।
 पाल-दाधवाव नरसंहार (Pal-Dadhvav massacre)	○ 7 मार्च को, गुजरात के पाल-दाधवाव नरसंहार की घटना को हुए 100 वर्ष पूरे हो गए। यह नरसंहार गुजरात क्षेत्र के इंदर रियासत के साबरकांठा जिले के पाल-चितरिया और दाधवाव गाँव में एक सदी पहले हुआ था। ➤ इसमें अंग्रेजों और सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए गए भू-राजस्व कर (लगान) के विरोध में आंदोलन किया गया था। ➤ इस नरसंहार में मेवाड़ भील कॉर्प्स के एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर एच. जी. सटन ने निर्दोष आदिवासियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था।



सुर्खियों में रहे स्थल

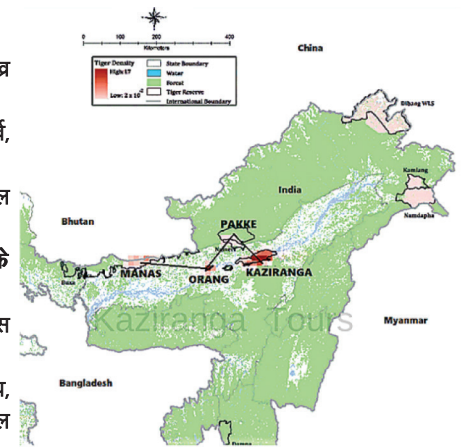
अमेज़ॅन वर्षावन

- नेचर क्लाइमेट चेंज में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार, अमेज़ॅन वर्षावन का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 2000 के दशक की शुरुआत से "टिपिंग पॉइंट" की ओर बढ़ रहा है।
 - टिपिंग पॉइंट्स: ये वे सीमाएं हैं जहां से एक छोटा सा परिवर्तन भी किसी प्रणाली को पूरी तरह से एक नयी स्थिति की ओर धकेल सकता है।
- अवस्थिति: यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह अमेज़ॅन नदी और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में विस्तृत है।
- सीमाएं (बाउंड्री):
 - यह ब्राजील के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। यह उत्तर में गुयाना उच्च भूमि, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।
 - यह लैंडलॉकड यानी स्थल-रुद्ध नहीं है।
- विशेषताएं:
 - इन वनों को "पृथ्वी का फेफड़ा" भी कहते हैं।
 - ये वन कार्बन सिक के रूप में काम करते हैं। कार्बन सिक ऐसे क्षेत्र होते हैं, जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे अधिक उसका अवशोषण करते हैं।
 - यह जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद करता है।



मानस राष्ट्रीय उद्यान:

- असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और गैंडों की आबादी में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।
- यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भी है।
- यह हिमालय की गिरीपदीय क्षेत्र में स्थित है। यह भूटान के सॉयल मानस नेशनल पार्क से संलग्न एक राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह मानस नदी के साथ-साथ विस्तृत है और उत्तर में भूटान के वनों से घिरा हुआ है।
- मानस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है।
- यह दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का पर्यावास भी है, जिसमें बाघ, एक सींग वाले गैंडे, स्वेप हिरण, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन शामिल हैं।



8468022022, 9019066066



www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



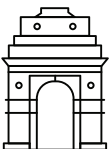
/Vision_IAS



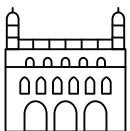
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



लखनऊ



जयपुर



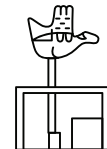
हैदराबाद



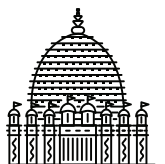
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी